



राज्य माहिती आयोग, मुख्यालय, मुंबई
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मधील कलम १९ (३) अन्वये
दाखल झालेले अपील

क्र. मुमाआ/नो. क्र. २००७१२/२०/अ. क्र. ५९८/२३/०१

श्री. राजेश वामन राणे

विरुद्ध

जन माहिती अधिकारी तथा सहाय्यक अभियंता (परि.२) जी/दक्षिण विभाग,
 बृहन्मुंबई महानगरपालिका, सहाय्यक आयुक्त, जी/दक्षिण विभाग यांचे कार्यालय,
 ५ वा मजला, धनमिल कंपाऊंड, एन.एम. जोशी मार्ग, परेल, मुंबई ४०० ०१३.

प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा विभाग कार्यकारी अभियंता जी/दक्षिण विभाग,
 बृहन्मुंबई महानगरपालिका, सहाय्यक आयुक्त, जी/दक्षिण विभाग यांचे कार्यालय,
 ५ वा मजला, धनमिल कंपाऊंड, एन.एम. जोशी मार्ग, परेल, मुंबई ४०० ०१३.

द्वितीय अपील अर्ज सुनावणी दिनांक : १६.०६.२०२३

अपीलकर्ता	:	उपस्थित
विद्यमान जन माहिती अधिकारी	:	उपस्थित
प्रथम अपीलीय अधिकारी	:	अनुपस्थित

मूळ अर्ज दिनांक	जन माहिती अधिकाऱ्याचा उत्तराचा दिनांक	प्रथम अपील दिनांक	प्रथम अपील आदेश दिनांक
०८.०८.२०१९	--	०१.१०.२०१९	२३.१०.२०१९

अपिलार्थी यांनी आयोगाकडे दि. ०५.०२.२०२० रोजीच्या अर्जान्वये प्रथम अपिल अधिकारी यांनी आदेश देऊन सुध्दा माहिती देण्यात आली नाही असे कारण नमूद करून द्वितीय अपील दाखल केले आहे.

अपिलार्थी यांनी त्यांचा अर्ज दि. ०८.०८.२०१९ अन्वये खालील माहिती विचारलेली आहे:-

A) Shum Improvement/1220 C.No.204 (1) Slum IMP-1 dt-11-07-2001

B) DMC/SP/Shum Improvement/536 dt-14-10-2003

C) ALT 2005 C N.107/ Slumeradi dt.-14-11-2005

D) DMC/SPLSlum fnaprovement/1015 dt-08-01-2001 संबंधित परिपत्रकाच्या

छायांकित प्रती मिळाव्यात.

२) वाणिज्यिक झोपडीवासियांच्या पात्रतेसाठी पालिका विभागाच्या दस्त ऐवज अथवा अभिलेख (पुराने) यांच्या निकषाची सविस्तर माहिती मिळावी.”

क्र. मुमाआ/नो. क्र. २००७१२/२०/अ. क्र. ५९८/२३/०१

अपिलार्थी यांनी द्वितीय अपील अर्जासोबत प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचे आदेश दिनांक २३-१०-२०१९ संलग्न केले आहेत.

प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी दि. २३-१०-२०१९ रोजी खालीलप्रमाणे आदेश दिले :

<p>“१) अपिलकर्ता यांनी</p> <p>(A) Slum Improvement/1220/ C. No.204 (1) Slum IMP-1 dt.11.07.2001.</p> <p>(B) DMC/SP ? Slum Improvement/536 dt.14.10.2003</p> <p>(C) ALT 2005 / C.N. 107 / Slumeradi dt. 14.11.2005</p> <p>D) DMC / SPL / Slum Improvement /1015 [dt.08.01.2004 संबंधित परिपत्रकाच्या छायांकित प्रती मिळण्याबाबत.</p> <p>२) वाणिज्यिक झोपडवासियांच्या पात्रतेसाठी पालिका विभागाच्या दस्तऐवज अथवा अभिलेख (पुरावे) यांच्या निकषाची सविस्तर माहिती मिळण्याबाबत दि.०८-०८-२०१९ रोजी माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये अर्ज केला होता.</p> <p>अपिलकर्त्यास जन माहिती अधिकारी यांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली असे नमुद करून दि. ०१.१०.२०१९ रोजी प्रथम अपिल अर्ज दाखल केले.”</p>	<p>“सुनावणी दरम्यान जन माहिती अधिकारी सहाय्यक / अभियंता (परिरक्षण-२) प्र. यांनी अपिलकर्त्यास क्र.सआजीद /१८८४१/ स.अ. (पर.) दि.२३-०८-२०१९ अन्वये माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वयेचा अर्ज वरिष्ठ वसाहत अधिकारी जी दक्षिण यांना वर्ग केल्याचे नमुद केले. सुनावणी दरम्यान वसाहत अधिकारी तथा जन माहिती अधिकारी उपस्थित होते. सदर माहिती ही वसाहत विभागाशी संबंधित नसल्याबाबत नमुद केले.”</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“जन माहिती अधिकारी यांनी उपरोक्त परिपत्रकाबाबत उपायुक्त (अतिक्रमण निर्मुलन) यांचे प्रशासकीय अधिकारी यांच्याकडून आदेश प्राप्त झाल्यापासून ०७ दिवसाच्या आत माहिती प्राप्त करावी. सदर माहिती उपलब्ध न झाल्यास माहिती गहाळ झाल्याबाबत परिपत्रक काढून महानगरपालिकेच्या सर्व विभागात विचारणा करून माहिती उपलब्ध झाल्यास त्याबाबतची माहिती अपिलकर्त्यास देण्याचे आदेश सुनावणी दरम्यान जन माहिती अधिकारी यांना देण्यात आले. याद्वारे आपला दि.०१.१०.२०१९ रोजीचा अपिल अर्ज निकाली निघतो.”

या प्रकरणी अपिलार्थी यांनी रस्ता रुदीकरणच्या कारणामुळे प्रकल्प बाधितांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी निर्गमित करण्यात आलेल्या परिपत्रकाची मागणी केलेली आहे. अपिलार्थी यांनी विशेष परिपत्रकांचे क्रमांक व दिनांक नमूद केलेले आहेत.

क्र. मुमाआ/नों. क्र. २००७१२/२०/अ. क्र. ५९८/२३/०१

सुनावणीच्या वेळी अपिलार्थी यांनी सादर केले की, त्यांना माहिती प्राप्त नाही. अपिलार्थी यांनी पात्रता निश्चितीबाबत एका प्रकरणामध्ये निश्चित केलेल्या पात्रताचे कागदपत्र सादर करून असे नमूद केले की, पात्रता निश्चित करतेवेळी परिशिष्ट-२ मध्ये संबंधित परिपत्रकाचा उल्लेख करण्यात आला आहे व त्या आधारावर त्यांनी परिपत्रकाची मागणी केलेली आहे.

माहिती अधिकारी तथा सहाय्यक अभियंता (परिरक्षण) जी/साऊथ यांनी संबंधित परिपत्रकची प्रत अपिलार्थीला १५ दिवसात उपलब्ध करून देणे.

या प्रकारचे परिपत्रक स्वयंप्रेरणेने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करणे आवश्यक आहे. उपायुक्त बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय यांनी या विषयासंबंधीचे परिपत्रक संकेतस्थळावर प्रकाशित झाले आहे किंवा कसे याचा आढावा घ्यावा. परिपत्रक प्रकाशित झाले नसेल तर १५ दिवसात प्रकाशित करण्याची कार्यवाही करावी.

सबब आयोग पुढील आदेश देत आहे:

माहिती अधिकारी तथा सहाय्यक अभियंता (परिरक्षण) जी/साऊथ यांनी संबंधित परिपत्रकची प्रत अपिलार्थीला १५ दिवसात उपलब्ध करून देणे.

या प्रकारचे परिपत्रक स्वयंप्रेरणेने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करणे आवश्यक आहे. उपायुक्त बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय यांनी या विषयासंबंधीचे परिपत्रक संकेतस्थळावर प्रकाशित झाले आहे किंवा कसे याचा आढावा घ्यावा. परिपत्रक प्रकाशित झाले नसेल तर १५ दिवसात प्रकाशित करण्याची कार्यवाही करावी.

आदेश

अपिल निकाली काढण्यात येत आहे.

मुंबई^१
दिनांक : १६.०६.२०२३



उल्लेख प्राप्तवाल
(सुनील पोरवाल)
राज्य मुख्य माहिती आयुक्त

